PROBLEM IN IMPLEMENTATION OF REVIVAL PLAN

*124. SHRI GURUDAS DAS GUPTA† :

SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of Textiles be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the proposed revival plan for the ailing NTC mills has gone away due to problems in its implementation; and

(b) if so, what are the details thereof and Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) and (b) Government approved a Turn Around Strategy for NTC mills involving, inter-alia, selective modernisation, financial restructuring and rationalisation of surplus workforce through the Voluntary Retirement Scheme. The strategy envisages an investment of Rs. 533 crores in modernisation; Rs. 689 crores for implementation of the Voluntary Retirement Scheme; Rs. 200 crores, in addition to normal budgetary support, to meet the requirements of liquidity and Rs. 50 crores for training and rehabilitation of workers proceeding on Voluntary retirement. The progress of the implementation of the Turn Around Strategy has been as follows: Modernisation schemes involving an outlay of Rs. 40.07 crores are under implementation; 26896 employees have availed of Voluntary Retirement Scheme as on 28-4-1993 from September, 1992; Rs. 100 crores has been released to meet the interim requirement of liquidity and rehabilitation schemes for workers availing of VRS have been approved and are under implementation. Since most of the NTC Subsidiaries have already made a reference to BIFR as per the provisions of Sick Industrial Companies (Special Provision) Act, 1985, any assistance that could be considered by financial institutions would have to be as part of the rehabilitation, package which may be cleared by BIFR.

*The question was actually asked on the floor of the House by Shri Gurudas Das Gupta.

SHRI SURESH KALMADI : Sir, what about Question No. 123 ?

MR CHAIRMAN : This has been postponed to the 12th May.

SHRI SURESH KALMADI : Will it be in the same sequence-third question ?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : Sir, the hon. Minister in his statement has said that Rs. 533 crore is the total volume of funds needed for modernisation of NTC mills, but he has not spelt out the sources from where the fund is coming. Is there any guarantee that this fund shall be available ?

Part (b) of my question is, he does not tell the House how the fund is going to be spent and what will be the impact. Therefore, I would like to know, is there any guarantee that the Government will be able to mobilise this money; and if so, how is it going to be spent ?

श्री जी. वेंकटस्वामी : सभापति जी, दिस इज सेम क्वश्चन आनरेबल मैंबर ने किया है कालिंग अटेंशन में, अगर यह सारी इन्फर्मेशन चाहते हैं तो मैं कालिंग अटेंशन में दे दूंगा । सभापति जी, वह अच्छी तरह से जानते हैं कि एन. टी. सी. की हालत क्या है ।

PROF. SAURIN BHATTACHARYA : This also can be discussed when we take up the Calling Attention.

श्री जी. वेंकट स्वामी : सभापति जी, उसमें मैं सारी इन्फर्मेशन आनरेबल मैंबर को दे दूंगा और उस समय सारा हाउस इसके ऊपर डिसकस कर सकेगा ।

MR. CHAIRMAN : Please ask something more specific in your second supplementary.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : My colleague will ask.

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, मंत्री महोदय के जवाब में आया है कि मात्र 40 करोड़ रुपया

only 40 crores of rupees have been given for modernisation, and the reason must be that we do not have sufficient funds. I am saying that they have hundreds of acres of very valuable lands. Will they auction these lands ? They will get, I think about Rs. 1,000 crores. Then they can modernise these mills.

The second part of my supplementary is this. There are 59 mills. Will the Government modernise them, and will they be asked to manufacture exclusively hank yarn to be given to the hank yarn bank so that we can solve the problem of the weavers also ?

These are two inter-related aspects of the question.

श्री जी. वेंकटस्वामी : सभापति जी, आनरेबल मैंबर को इन्फर्मेशन तो मैं काफी दे चुका हूं अपने रिटन स्टेटमेंट में और माडर्नाइजेशन के लिए जो पैसा गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने डिसाइड किया है 533 करोड़ रुपया ....

श्री चतुरानन मिश्र : वह तो लिखा हुआ है। हमने यह नहीं पूछा । हमने यह पूछा कि इनके पास सैंकड़ों एकड़ जमीन है, वह जमीन को बेच देते, उसको ऑक्शन करके, उस रुपए से इनका जल्दी से जल्दी माडर्नाइजेशन कीजिएगा और जो माडर्नाइज करेंगे वह मिला जो गवर्नमेंट की है हैंकयार्न प्रोड्यूस करके क्या आप मिलों को देंगे ? यही मेरे दो क्वश्चन हैं ।

श्री जी. वेंकटस्वामी : सभापति जी, उसका आनरेबल मैंबर ही पहले उसके पहले जो आप सजेशन कर रहे हैं इसको यह हाउस में, वह हाउस में, दोनों में भी वर्कर्स की एजीटेशन की वजह से पहले से मेरे से पहले जो मिनिस्टर थे इस प्रोपोजल को रखा कि आधा प्रोपर्टी ही बेचें और माडर्नाइज करें। इसके सिवाय कोई चारा नहीं है । इसके लिए वर्कर्स का एजीटेशन आया उस पर यह हुआ कि हाउस के सामने मिनिस्टर को कहना पड़ा कि हम अभी नहीं बेचेंगे और जो एक टर्न आउट प्लान बनायेंगे और प्लान के तहत माडर्नाइजेशन करेंगे । उस वक्त सोचा जाएगा, अब इस वक्त एन. टी. सी. 124 मिल्स बहुत सारे सिक हैं । इसका सही मायनों में इस इंडस्ट्री को रखना और चलाना यह गवर्नमेंट का इंटेंशन है। अगर यह दोनों भी करना है तो जो रास्ता आनरेबल मैंबर हमको सजेस्ट कर रहे हैं उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है ।

श्री चतुरानन मिश्र : अगर दूसरा रास्ता नहीं है तो इस रास्ते पर आप क्यों नहीं चलते ?

श्री जी. वेंकटस्वामी : आप लोग इजाजत दें ।

श्री चतुरानन मिश्र : देखिए, इजाजत तो हम दे रहे हैं । हमारी बिना इजाजत के आपने 26 हजार मजदूरों का वालंटरी रिटायरमेंट कर दिया, लेकिन किसी हाउस में नहीं कहा था कि 26 हजार मजदूरों को काम से निकाल दीजिए । अगर यही एकमात्र रास्ता है तो कहिए कि इसको मानेंगे ?

श्री जी. वेंकटस्वामी : सभापति जी, आनरेबल मैंबर सजशन तो दे रहे हैं कि इंडस्ट्री वायएबल हो और प्रोडक्टिविटी के ऊपर प्रोफिट आए, तो कैसा वायएबल हो सकता है आनरेबल मेंबर को मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके साथ ट्रेड यूनियन में 45 ईयर्ज रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं इंडस्ट्री की कैपेसिटी के लिहाज से वर्किंग क्लास होना चाहिए और एक्स्ट्रा वर्कर्स को रख कर आप कब तक चलायेंगे और इंडस्ट्री को कब तक सिक करते रहेंगे । इसलिए मैं योजना बना रहा हूं, आप मैंबरों से कमेंट लूंगा, आप लोगों से डिसकस करुंगा हर इंडस्ट्री के बारे में कैसा वायएबल हो सकता, कितने वर्कर्स रह सकते हैं और कितने वर्कर्स रहने से इंडस्ट्री में प्रोफिट आ सकता है ।

SHRI CHATURANAN MISHRA : This is not the question I am asking him, Sir.

MR. CHAIRMAN : You please debate it in the Calling Attention which is coming up.

SHRI CHATURANAN MISHRA : I have no objection to that. I just wanted a clarification. If you help me, they will reply.

I have asked a specific question whether the Government has decided to sell those lands. If not why not ? That will give them money to modernise the plan. That is first part of my question. Secondly, those mills which are modernised should produce hanked yarn to be given to the weavers.

श्री जो. वेंकटस्वामी : हैंकयार्न ईवन टूडे सभापति जी, आज भी हैंकयार्न एन. टी. सी. की मिलों में जो तैयार हो रहा है, हैंडलूम वीवर्ज को जा रहा है जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसमें हैंकयार्न भी परसेंटज के लिहाज से ज्यादा है । सभापति जी, और एक सवाल उन्होंने कहा है, मैं मिनिस्ट्री में आने के बाद आनरेबल मैंबर्स को मैंने ऑफर किया है कि पूरे देश के एन. टी. सी. के वर्किंग क्लास के लिए यह जो इंडस्ट्री है वर्कर्स कोआपरेटिव बना कर सब ले लें और चलाएं । हम तो गवर्नमेंट की तरफ से देने को तैयार हैं, लेकिन पहले आप इसको मान लें ।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Let the Government be run on cooperative basis. Let the Reserve Bank be run on the cooperative basis. Let the STC be run on the cooperative basis. The Minister need not give us sermons.

(*Interruptions*)

श्री जी. वेंकट स्वामी : सभापति जी, आनरेबल मैंबर्स का यह स्लोगन था कि मजदूर भी मालिक बनें, तो मालिक बनने के लिए आज हम कह रहे हैं ।

श्री प्रमोद महाजन : मालिक बनने के लिए बीमार मिल क्यों दे रहे हैं ? मालिक बनने के लिए आप बीमार मिल क्यों दे रहे हैं ?

Why do you give sick mills ? (*Interruptions*).

श्री मूल चन्द मीणा : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह एन. टी. सी. मिलों के रुग्ण अवस्था में आने के क्या कारण थे ? दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपके जो मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण जो मिल रुग्ण हैं उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं तो क्या कारण हैं ?

श्री जो. वेंकटस्वामी : सभापति जी, यह कारण तो सारा देश जानता है मिल मालिकों ने इनका रस चूस लिया और छोड़ दिया । एन. टी. सी. उसके सहारे में आया । मजदूरों को नुकसान न हो, मजदूरों की छंटनी न हो और मजदूरों के लिए कंटीन्यूएनश कई सौ करोड़ रुपया गवर्नमेंट का जा रहा है । जो बिलो पावर्टी लाइन है, मजदूरों का भी इसमें ब्लड जा रहा है । इसको सोचने की जरूरत है । तो हमको आज निर्णय करने की जरूरत है सभापति जी, कि 30 परसेंट बिलो पावर्टी लाइन में जो लोग हैं, वह बजट दे रहे है यह आर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास के लिए हम कितने रोज आइडियल वज देकर बैठेंगे आपको एक न एक रोज निर्णय करना पड़ेगा । इस आइडियल वेज को गवर्नमेंट आफ इंडिया पे करती आ रही है । फिर यहां पूछा जाता है कि कौन जिम्मेदार हैं इसके । जिम्मेदार वह हैं जो कई सालों से इंडस्ट्री में हैं। 120 सालों से भी ज्यादा से इंडस्ट्री में हैं ।

SHRI PRAGADA KOTAIAH : Sir, I would like to know.. .....

MR. CHAIRMAN : I have called another Member. You please sit down.

श्री मोहम्मद अमीन : सर, मैं आपके जरिए से आनरेबल मिनिस्टर से यह जानना चाहता हूं, सर, मुझे यह पूछना है कि कार्पोरेशन की कितनी सिक मिलों को बी.आई. एफ. आर. में रैफर किया गया है ?

Referring the cases to BIFR is not a solution in my opinion. Therefore, I would like to know if the Government is considering to take out those cases from the BIFR, sit with the Central Trade Unions and find out ways and means to make them viable. What is the plan for this ?

श्री जी. वेंकट स्वामी : सभापति जी, यह एन. टी. सी. को 9 सबसिडरिज हैं जिसमें से 7 सबसिडरिज बी. एफ. आई. आर. को रैफर हो गए हैं। अब एक और सबसिडरी भी जाने के रास्ते पर है, न मालूम आज या कल वह भी चला जाए। एक तमिलनाडु सबसिडरि बाकी रह जाएगा। ....(**व्यवधान**).... आप कालिंग-अटेंशन में बात करो न! प्लीज, मुझे बोलने दो। मुझे जवाब देना है मेम्बर को। तो सभापति जी, मैं ऑनरेबिल मैम्बर को मालूम कराना चाहता हूं कि बी. आई. एफ. आर. से विदड्रा करने का हक हमें नहीं है गवर्नमेंट को, जब यह जा चुका है। यह हो सकता है, वर्किंग क्लास, फ्यूचर प्रोडक्टिविटि वगैरह उनको सेटिसफाई हुआ तो वह परमिट कर सकते हैं और उस प्रोसेस में हम हैं। उस प्रोसेस में जाकर बी. एफ. आई. आर. से डिसकस कर रहे है फ्यूचर मोडर्नाइजेशन प्रपोजल।

श्री अजीत जोगी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह अध्ययन अब पूरा हो गया है कि एन. टी. सी. की जो 124 मिलें हैं, उनमें से कितनी वास्तव में रिवाइव की जा सकती है और कितनी को वास्तव में बंद करना पड़ेगा? और, मध्यप्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश में जो मिलें हैं, क्या यह सच है कि तीन मिलों को उनमें से आपने बंद करने का फैसला कर लिया है। यदि कर लिया है तो मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इन मिलों में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है? जो वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, वह किस प्रकार की होगी?

श्री जी. वेंकटस्वामी : सभापति जी, ऑनरेबिल मैम्बर को मैं यह बता देना चाहता हूं कि कोई तीन मिल ही नहीं बल्कि 14 मिल ऐसी है, जो क्लोजर की नौबत में हैं। इनमें मध्यप्रदेश की भी एक दो मिल आ सकती हैं। तो ऐसी मिलों को भी चलाया जा सकता है क्या, इसकी हम जांच कर रहे हैं और टोटल योजना 124 मिल की हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें 13 टेकओवर मिल हैं, बाकी जो हैं एन. टी. सी. की मिलें हैं। मैं ऑनरेबिल मैम्बर को बताना चाहूंगा कि जब कभी ऐसी कोई बात आई, क्लोज करने की बात आई, तो हाऊस के सामने लाएंगे।

SHRI AJIT P. K. JOGI : That means every worker will be without any alternative employment. Is that an assurance given by the Minister ?

श्रीमती सत्या बहिन : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि सरकार ने जो रुग्ण मिलों के आधुनिकीकरण की व्यवस्था की है, इसकी जो योजना बनाई है, तो इसमें निश्चित रूप से नई एडवांस टैक्नोलोजी का उपयोग होगा? जब नई टैक्नोलोजी का उपयोग होगा तो उसमें श्रमिकों के विशेष प्रशिक्षण की भी व्यवस्था अवश्य होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं यह जानना चाहती हूं कि इसमें विशेष प्रशिक्षण के लिए सरकार ने कोई योजना श्रमिकों के लिए बनाई है या नहीं बनाई है? उसमें महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? इसके साथ क्या उनके वेतन में भी कोई वृद्धि होगी या नहीं होगी?

श्री जी. वेंकट स्वामी : सभापति जी, जब मोडर्नाईजेशन होगा, नई टैक्नोलोजी होगी तो जरूर ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसमें लेडीज को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्रीमती सत्या बहिन: वेतन में वृद्धि होगी या नहीं होगी? यह भी बताइए।....(**व्यवधान**)....

SHRI VIREN J. SHAH : Mr. Chairman, Sir, we are having a calling attention on this question. We can go to the next question.

MR. CHAIRMAN : Q. No. 125.

EFFECT ON INDIGENOUS INDUSTRY OF REDUCTION OF IMPORT DUTY

*125. SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the Government are aware that reduction in import duties on projects and capital goods have affected the indigenous industry since no methodology has been evolved for certification of eligibility to import raw materials and components and discharge of bond for duty differential.